शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 19 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 29 – 6 मई 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या सुक्खू का आनन्द प्रयोग वांछित परिणाम दे पायेगा

- आनन्द के लिये कांगड़ा और हमीरपुर एक जैसे हैं क्या हमीरपुर से उम्मीदवार होना ज्यादा सन्देशपूर्ण नहीं होता
- उम्मीदवारों के चयन में लगे समय से भी यही सन्देश गया है कि आनन्द और रायजादा पहली पसन्द नहीं थे?

शिमला/शैल। कांग्रेस ने लम्बे मंथन के बाद कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिये अपने उम्मीदवार नामित किये हैं। कांगड़ा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनन्द शर्मा और हमीरपुर से ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को प्रत्याशी बनाया गया है। स्मरणीय है कि हमीरपुर से उपमुख्यमंत्री मुकेश अगिनहोत्री और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री तथा कांगड़ा से विधायक आर. एस.बाली के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में इतने चर्चित

हुये की तीनों को रिकॉर्ड पर अपनी असमर्थता जाहिर करनी पड़ी। इस असमर्थता के बाद सतपाल रायजादा और आनन्द शर्मा के नाम सामने आये। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह नाम पार्टी की पहली पसन्द नहीं थे। हमीरपुर में कांग्रेस का मुकाबला वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से है। अनुराग ठाकुर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के सबसे अधिक मुख्य आलोचक हैं और हमीरपुर से पांचवीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आते हैं। ऐसे में अनुराग ठाकुर को एक कड़ी चुनौती पेश करना कांग्रेस की राजनीतिक आवश्यकता मानी जा रही थी। लेकिन रायजादा यह चुनौती पेश कर पाएंगे इसमें संदेह माना जा रहा है। क्योंकि सुक्खू सरकार के अब तक के कार्यकाल में सरकार के किसी भी मंत्री और संगठन के पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री तो दूर अनुराग ठाकुर तक से कभी कोई कठिन सवाल नहीं उठाया है। बल्कि कांग्रेस की इसी कार्यशैली के कारण हमीरपुर के चुनाव को कुछ क्षेत्रों में मैच फिक्सिंग की संज्ञा भी दी जाने लगी है।

इसी के साथ कांगड़ा से आनन्द शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर भी कई सवाल उठने लग पड़े हैं। क्योंकि आनन्द शर्मा 1982 के बाद प्रदेश की चुनावी राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं। आनन्द शर्मा के खिलाफ 1982 में ही हरियाणवी होने का सवाल उठा था। आनन्द शर्मा लम्बे अरसे तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। हिमाचल और राजस्थान से दो – दो बार राज्यसभा में नामित हो चुके हैं। केंद्र में बतौर मंत्री बहुत सफल रहे हैं। इसी सफलता के कारण वह गांधी परिवार के अति विश्वसतों में गिने जाते रहे हैं। इसी विश्वसत्ता के कारण हिमाचल की राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू उन्हीं के आशीर्वाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे थे। आनन्द शर्मा ने अपनी सांसद निधि से सुक्खू और विप्लव ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में भी सहयोग किया है। हालांकि मुंबई में अंबानी के कैंसर इंस्टिटयूट को सांसद निधि देने पर सवाल भी झेल चुके हैं।

शायद इसी पृष्ठभूमि के चलते वह कांग्रेस के जी – 23 समूह के बड़े नाम हो गये थे। अभी जब प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिये उम्मीदवार तय होने की कसरत चल रही थी तब आनन्द शर्मा ने बड़ी बेबाकी से कांग्रेस के जाति जनगणना के प्रस्ताव पर गंभीर सवाल उठाते हुये हाईकमान को पत्र लिख दिया था। प्रदेश कांग्रेस की कई महत्वपूर्ण बैठकों से नदारद भी रहे हैं। यहां तक चर्चाएं आ गयी थी कि वह अब गांधी परिवार के विश्वस्तों की सूची से बाहर हो गये हैं। समरणीय है कि जब जी – 23 समूह की चर्चा उठी थी तब उसमें एक नाम ठाकुर कॉल सिंह का भी सामने आया था। तब कॉल सिंह ने रिकॉर्ड पर यह कहा था कि उनसे किसी और प्रस्ताव के नाम पर दस्तखत करवाये गये थे। लेकिन उनका प्रयोग किसी और संद्धर्भ में कर लिया गया। कॉल सिंह के स्टैंड के बाद हिमाचल से किसी भी अन्य नेता का नाम जी – 23 में शामिल नहीं हो पाया। इस कारण आनन्द शर्मा की जी – 23 में भी सक्रियता आगे नहीं बढ़ पायी और वह एक तरह से तटस्थता की भूमिका में चले गये।

अब जब राज्यसभा चुनाव में सरकार को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और तब शायद कांग्रेस हाईकमान को प्रदेश के बारे में अपना आकलन बदलना पड़ा। इसका संकेत पर्यवेक्षकों ने भी यह कह कर दे दिया था की नेतृत्व के प्रश्न पर चुनावों के बाद चर्चा होगी। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक हाईकमान इस सवाल का जवाब अभी तक तलाश नहीं पाया है कि कांग्रेस में हुये विद्रोह का केंद्र हमीरपुर और ऊना ही क्यों बने हैं? इसी वस्तुस्थिति में हाईकमान में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। इसी परिदृश्य में प्रदेश के सारे चुनाव की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर छोड़ दी गयी थी। उम्मीदवारों का चयन और उनकी चुनावी जीत सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री और उनके मित्रों की जिम्मेदारी हो गयी है। इसी परिप्रेक्ष में यदि आनन्द शर्मा की कांगड़ा से उम्मीदवारी का आकलन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यह चयन मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला रहा है। क्योंकि यदि आनन्द शर्मा हाईकमान की पसन्द होते तो उन्हें हिमाचल में भी अनुराग ठाकुर के मुकाबले हमीरपुर से उम्मीदवार बनाया जाता। आनन्द के लिये कांगड़ा और हमीरपुर दोनों एक जैसे ही हैं। हमीरपुर से उम्मीदवार बनने से यह सन्देश जाता कि कांग्रेस ईमानदारी से अनुराग को रोकना चाहती है। लेकिन यह सन्देश कांग्रेस दे नहीं पायी है।

इस समय आनन्द शर्मा राज्यसभा में नामित न हो पाने

के कारण राजनीतिक हाशिये पर जा पहुंचे हैं। इसीलिये गगल हवाई अडडे पर उनके स्वागत के लिये कोई ज्यादा भीड़ नहीं हो पायी और न ही चम्बा के नेता आ पाये। कांगड़ा का नेतृत्व आनन्द को कितना सहयोग दे पायेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि जब सुधीर शर्मा ने बैजनाथ से धर्मशाला शिफ्ट किया था तब उनके खिलाफ भी बाहरी होने का आरोप लग गया था। आनन्द तो हरियाणा और फिर शिमला से बंधे हैं। यही नहीं राज्यसभा सांसद रहते हुये वह किसी एक स्थान से बन्ध ही नहीं सकते। लेकिन लोकसभा के लिये इस तर्क से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तो छूट सकते हैं परन्तु आनन्द शर्मा नहीं। इसलिये यही माना जा रहा है की सुक्खू ने आनन्द को फिर से गांधी परिवार में स्थापित करने के लिये यह प्रयोग किया है।

राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर दीक्षांत समारोह को सम्बोधित भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल आगमन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले मेधावियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह एक यादगार पल होता है जो विद्यार्थियों को भविष्य में प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है और अपने संस्थान के अविस्मरणीय क्षणों की याद दिलाता है।

उन्होंने कहा कि यह क्षण रचनात्मकता, ज्ञान और निरंतर सीखने की अभिलाषा की शुरूआत है। उन्होंने कहा कि सभी मेधावियों के लिए यह आत्ममंथन का दिन है ताकि कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान की जा सके।

राज्यपाल ने कहा कि उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की समाज, देश और राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें पूर्ण निष्ठा से इस भूमिका को निभाना है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से अर्जित ज्ञान का उपयोग वे समाज के हित में करें। विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा का महत्व जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करना होता है। ज्ञान हमें दूसरों के लिए निज हितों का त्याग करना सिखाता है। उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है और उनकी शिक्षाएं समाज पर दूरगामी प्रभाव डालती है। शिक्षक वह आधार है जिस पर एक शिक्षित और सभ्य समाज की नई पौध विकसित होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को इस ढंग से ढालना चाहिए ताकि वे समाज में सुशिक्षित, ईमानदार और जागरूक नागरिक की भूमिका निभा सके।

उन्होंने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में विद्यार्थियों को अपने कार्य में गुणवता और गतिशीलता बनाये रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए ई-शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान में नई उंचाईयां हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि मेधावी विद्यार्थी विश्व में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर सके।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की।

राष्ट्रपति का शिमला पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत

शिमला/शैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का शिमला पहुंचने पर मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वागत किया।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राष्ट्रपति के दौरे के लिए मिनिस्टर-इन-वेटिंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार तथा प्रदेश सरकार एवं सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन और एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 'असेसमेंट ऑफ फिस्कल रिस्क ड्यू टू डिजास्टर इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर' विषय पर प्रमुख विभागों एवं अन्य हितधारकों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आपदाओं के कारण परिवहन (सड़क एवं पुल)और ऊर्जा (विद्युत) जैसे क्षेत्रों की आवश्यक अधोसंरचना पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों के दृष्टिगत राजकोषीय जोखिम मूल्यांकन ढांचे को विकसित करने पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर विशेष सचिव राजस्व डी.सी. राणा ने भविष्य की आपदाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र और विभागों की तैयारियों के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता से अवगत करवाया। उन्होंने वर्ष 2023 की बाढ़ के बाद आपदा मूल्यांकन और पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

योजना सलाहकार बसु सूद ने आपदा क्षति और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण में वित्त पोषण अंतर पर प्रकाश डाला।

एडीपीसी के उप-कार्यकारी निदेशक असलम परवेज ने अधोसंरचना और सांख्यिकीय विश्लेषण व्यय, योजना, ऊर्जा, परिवहन और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सके।

सीडीआरआई की रंजिनी मुखर्जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जो महत्वपूर्ण अधोसरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार के लिए सहायक होंगे। कार्यशाला में विभिन्न सरकारी विभागों, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी एजेंसियों 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में जलवायु और आपदारोधी बुनियादी ढांचे के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढीकरण करने पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में नौणी विश्वविद्यालय ने जीते छह पुरस्कारों

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नेरी और नौणी परिसरों के छात्रों और वैज्ञानिकों का हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'खाद्य प्रसंस्करण 4.0:नवाचार और स्थिरता' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शानदार प्रदर्शन किया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के छ: संकाय और 26 स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया।

खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा ने 'खाद्य प्रसंस्करण: नवाचार और स्थिरता' पर एक व्यावहारिक व्याख्यान दिया और 'कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और न्यूट्रास्यूटिकल्स' पर केंद्रित एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की। सहायक प्रोफेसर डॉ. अभिषेक ठाकुर को उनके पेपर 'वेस्ट टू वर्थ यूटिलाइजेशन ऑफ वास्प-अफेकटेड एप्पल वराइटि अन्ना का हिमाचल प्रदेश के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चिप्स बनाने के लिए' शीर्षक के लिये सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति पुरस्कार से नवाजा गया।

विश्वविद्यालय की सफलता में और योगदान देते हुए, डॉक्टरेट स्कॉलर अनुपमा आनंद और हरप्रीत कौर सैनी ने अपने संबंधित शोधपत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति पुरस्कार जीता। अनुपमा ने 'मकई के वेस्ट से माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलूलोज़ पर विभिन्न निष्कर्षण तकनीकों के प्रभाव की जांच' और हरप्रीत ने ' मकई रेशम का इन विट्रो अध्ययन से उसकी मधुमेह विरोधी और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता पर प्रस्तुति दी। दो अन्य डॉक्टरेट स्कॉलर मोनिका ठाकुर और पूजा सोनी ने भी सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार हासिल करके अपनी शोध उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। मोनिका के पेपर, 'एलोवेरा जेल के साथ कार्यात्मक रूप से मजबूत कम कैलोरी वाले मफिन का निर्माण और मूल्यांकन', और पूजा के 'ऑस्मोटिक डीहाइड्रेटेड सैंड पियर चिप्स का निर्माण' पर पोस्टर प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त, एमएससी की छात्रा अनिका पंवार ने 'चिटोसन नैनोइमल्शन - आधारित बायोएक्टिव फिल्में: उत्पादन और लक्षण वर्णन' शीर्षक वाले अपने पेपर के लिए सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार प्राप्त किया। विश्वविद्यालय प्रशासन और विभाग के वैज्ञानिकों ने सभी विजेताओं को बधाई दी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मतदान के दिन लगाई जाएगी एनसीसी कैडेटों की ड्यूटी

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने पुलिस और नेशनल कैडेट कोर की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा आम चुनावों और 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों के लिए एनसीसी कैडेट्स को 1 जून, 2024 (मतदान दिवस) को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आयोग का यह कदम युवाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे युवा कैडेटों में निःस्वार्थ सेवा की भावना का संचार भी होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्धता के आधार पर तीन कैडेट तैनात किए जाएंगे और यह तैनाती पूर्ण रूप से स्वैच्छिक आधार पर होगी। उन्होंने बताया कि कैडेट की तैनाती का स्थान उनके संबंधित बीट/जिले के भीतर ही होगा। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर कैडेट वर्दी व बिना हथियारों के तैनात किए जाएंगे, जो यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, वृद्ध और दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता जैसे गैर सुरक्षा संबंधी दायित्वों में पुलिस कर्मियों या गृह रक्षकों की सहायता करेंगे।

उन्होंने कहा कि तैनात कैडेट को चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य मतदान कर्मियों के समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिदिन 150 रुपये या पैक्ड लंच दिया जाएगा और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी उनके परिवहन की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में यह कैडेट्स अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। बैठक में एनसीसी के ग्रुप कमांडर कर्नल ए.एस. बैंस से सीनियर डिवीजन के 18 वर्ष से अधिक आयु के कैडेट्स का जिला/यूनिटवार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया, ताकि उनकी इच्छा और माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें उपयुक्त रूप से तैनात किया जा सके। तैनात किए जाने वाले कैडेट्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुये लोकसभा तथा विधानसभा उप-चुनावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों 2024 के लिये 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन उसी दिन प्रात: 11.00 बजे शुरू होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई होगी। छंटनी प्रक्रिया 15 मई को तथा नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 17 मई, 2024 होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया और इसके संबंध में विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच किसी भी समय दाखिल किये जा सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार चार से अधिक नामांकन पत्र नहीं भर सकेगा।

उन्होंने इन चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से मतदान दिवस पर अनिवार्य सेवाओं पर तैनात विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए शिमला में स्थापित स्टेट क्लीयरिंग सेंटर के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सेंटर पर बिना अंकित किए एवं डाले गए डाक मत पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक मत पत्रों (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से मतदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों तथा डाक मत पत्रों द्वारा 85 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, कांग्रेस के एल.एस. मेहता, नरेश वर्मा, भाजपा के शुभम सिंह गुलेरिया, सीपीआई (एम) के सुनील वशिष्ट, बहुजन समाज पार्टी के अनिल कपूर तथा निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

हार सामने देखकर चुनाव लड़ने से पीछे हटे जयराम:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खू ने बंजार में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के लिए वोट मांगते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हार सामने देखकर लोकसभा चुनाव लड़ने से पीछे हट गये। उन्हें मालूम था कि पांच साल मुख्यमंत्री रहते मंडी संसदीय क्षेत्र में काम नहीं रनौत को टिकट दिला दी। कंगना को फेल करने में जयराम ठाकुर का पूरा सहयोग रहेगा। कंगना रनौत एक महीने की शूटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश आयी हैं। नेता प्रतिपक्ष जितनी मर्जी लोकेशन सेट कर लें, जितनी लोकेशन बदल लें, फ़िल्म फ्लॉप होना तय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां टॉप का हीरो (विक्रमादित्य सिंह) है।

किया है, वह सिर्फ सराज तक ही सीमित रहे। ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि हाईकमान के बोलने पर पहले जयराम ने चुनाव लड़ने की हामी भर दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पता चला कांग्रेस युवा व स्मार्ट चेहरे विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारने वाली है, वह पीछे हट गये। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कहा कि मंडी से कोई सेलिब्रिटी ही जीत सकती है, इसलिये कंगना

टॉप का हीरो वह होता है जो दिन-रात जनता की सेवा में लगा रहता है। विक्रमादित्य सिंह ने आपदा में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का भरपूर साथ दिया है। वह लोगों के दुख में साथ खड़े हुये। जेसीबी में बैठकर सड़कों को खुलवाया व वैली ब्रिज बनवाये। विक्रमादित्य ने बंजार में अनेक कार्य किये हैं, सांसद बनकर वह यहां विकास की गंगा बहायेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद वह विक्रमादित्य सिंह के साथ फिर बंजार आएंगे और लोगों की मांगों को पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खोल रखे थे। नौकरियां बेची जाती थीं और जयराम ठाकुर पूरे पांच साल मूकदर्शक बने रहे। भाजपा हिमाचल व महिला विरोधी है। पहले आपदा में साथ नहीं दिया, फिर महिलाओं के 1500 रुपये रुकवाने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गये। भाजपा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करती है। कांग्रेस काम करने में विश्वास रखती है, भाजपा की तरह चुनाव देखकर धन आवंटन नहीं करती। भाजपा ने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायक खरीदकर भी जयराम सत्ता की भूख नहीं मिटा पाये। कांग्रेस के पास पैसा नहीं जनबल है। जनबल की ताकत से ही धनबल को हराएंगे।

बंजार में पूर्व कर्मचारियों ने कांग्रेस का दामन थामा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खू व लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने सेवानिवृत्त असिस्टेंट प्रोफेसर जोगिंदर ठाकुर, सेवानिवृत्त मुख्य शिक्षक सबजा चंद, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री की नीतियों व कार्यो में आस्था जताते हुए कांग्रेस जवाइन की है।

अनुराग ठाकुर ने सांसद रहते कुछ नहीं किया:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खू ने कहा कि बिकाऊ विधायक जनता के सबसे बड़े गुनहगार हैं। उन्होंने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर चुनाव का अनावश्यक बोझ डाला है। सवाल सरकार, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी का नहीं है, जनता के वोट के निरादर का है। लोकसभा चुनाव में 1 जून को नादौन से ऐसी आवाज पूरे प्रदेश में जानी चाहिए कि नोट के दम पर सरकार गिराने की कोशिश करने वाली भाजपा को सबक मिले। बिकाऊ विधायकों ने अपने आप को राजनीतिक मंडी में बिकने के लिए छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने ये बातें नादौन विधानसभा क्षेत्र के बड़ा, पुतड़ियाल व नौहंगी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद रहते अनुराग ठाकुर ने कुछ नहीं किया। आपदा के समय वह प्रभावितों के साथ खड़े नहीं हुये। एनपीएस के 9000 करोड़ रुपये दिलाने में कोई मदद नहीं की। जोलसप्पड़ मेडिकल कॉलेज पर अनुराग झूठ बोलते हैं, इसे उन्होंने नहीं मैंने स्वीकृत करवाया है। अगर उन्होंने मंजूर करवाया होता तो वह हमीरपुर में खोलते 16 किलोमीटर दूर जोलसप्पड़ में नहीं खुलने देते। मेडिकल कॉलेज के साथ ही कांग्रेस सरकार कैंसर अस्पताल भी खोलने जा रही है। 5 करोड़ रुपये का बजट जारी हो चुका है। बड़ा के सधोड़ा पत्तन में ब्यास नदी पर पुल बनाने के लिए 10 करोड़ का बजट सरकार दे चुकी है। चुनावों के बाद इस पुल का नींव पत्थर रखा जायेगा। नादौन के खरीदी मैदान में 100 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जिसमें 6-7 खेलों को खेला जा सकेगा। दर्जनों युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवा पीढ़ी को नशे से बचाएंगे। बड़ा में पूर्व यूपीए सरकार में मंजूर स्पाइस पार्क में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि उस जमीन पर क्या हो सकता है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि नादौन की सड़कें बेहतर बनाने के लिए बजट जारी हो चुका है। छः महीने में सभी आईपीएच स्कीमों की सूरत बदल जाएगी। गर्मियों में पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे। कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में 22 हजार सरकारी रोजगार निकाले हैं। 20 साल पहले आपने पहली बार विधायक बनने का मौका दिया। नादौन की जनता सदैव मेरे साथ खड़ी रही। जो पौधा आपने लगाया था वह वृक्ष बन चुका है, अब उसका फल खाने का समय है। नादौन के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा के लिए अधिक से अधिक मतदान करें।

आनंद शर्मा ने देश-विदेश में हिमाचल का नाम चमकाया, प्रदेश-कांगड़ा को अनेक सौगातें दे चुके:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पूछा, भाजपा बताये वर्तमान सांसद व गद्दी नेता किशन कपूर का टिकट कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से क्यों काटा गया। बीते लोकसभा चुनाव में वह सबसे अधिक मतों से जीते थे। इतना अधिक मतदान उनके पक्ष में होने के बावजूद गद्दी नेता का टिकट काटना कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता को अखर रहा है। भाजपा ने कांग्रेस के एक बिकाऊ विधायक को विधानसभा उपचुनाव में टिकट दे दिया, जबकि गद्दी नेता किशन कपूर हाशिये पर धकेल दिये।

धर्माणी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने देश-विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम चमकाया है। वह केंद्रीय मंत्री रहते प्रदेश व कांगड़ा जिला को अनेक सौगातें दे चुके हैं। उन्होंने कांगड़ा जिला के इंदौरा में डेढ़ सौ करोड़ रुपये की सौगात देकर इंडस्ट्रियल पार्क खुलवाया। चाय बागवानों के लिए नेशनल टी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मंजूर करवाया। कांगड़ा जिला के पालमपुर में वह सेरीकल्चर विस्तार केंद्र भी खुलवा चुके हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पासपोर्ट कार्यालय की सौगात भी दी है। इससे पहले प्रदेश के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए चंडीगढ़ या अन्य जगह जाना पड़ता था। शिमला में कार्यालय खुलने के बाद से लाखों पासपोर्ट बन चुके हैं। आनंद शर्मा की यह प्रदेश को बड़ी देन है। उन्होंने पूरे राज्य में सड़क निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं अन्य विकास कार्यो के लिए करोड़ों रुपये की राशि सांसद निधि से प्रदान की है। आईआईटी मंडी का नींव पत्थर उन्होंने रखा है। आनंद शर्मा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नेरचौक व आईआईआईटी ऊना जिला को दिलाने में मदद की। केंद्रीय मंत्री रहते चंबा, नाहन व हमीरपुर मेडिकल कॉलेज दिलाने में भी उनका सहयोग रहा है।

धर्माणी ने कहा, आनंद शर्मा ने यह विकास कार्य इसलिए नहीं किए कि उन्हें चुनाव लड़ना था। आनंद शर्मा ने प्रदेश में विकास को और गति देने के लिए यह काम किये। उन्होंने अपनी राज्यसभा की सांसद निधि पूरे प्रदेश में वितरित की है।

भाजपा के सांसद हिमाचल का विकास करवाने में पूरी तरह विफल रहे। आपदा में उन्होंने जनता का साथ नहीं दिया, न ही प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज मांगने की हिम्मत जुटा पाये। आनंद शर्मा जिस भी मंत्रालय में यूपीए सरकार में मंत्री रहे, उसमें सराहनीय कार्य किया। हिमाचल के जितने भी मंत्री केंद्र में रहे हैं, उनमें सबसे अधिक व बेहतरीन काम आनंद शर्मा ने किया है। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री तो राजनीतिक रोटियां सेंकने में ही व्यस्त रहते हैं।

कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचायें कार्यकर्ता:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह सांसद बनने के

बाद मण्डी संसदीय क्षेत्र को उत्कृष्ट संसदीय क्षेत्र बनाने में कोई कोर कसर बाकी नही रखेंगे। विक्रमादित्य के पास अनुभव के साथ साथ आधुनिक सोच का विजन है और वह सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ेंगे।

रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने तीन बार इस संसदीय क्षेत्र का सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सांसद निधि का पूरा सद्पयोग किया। महिला उत्थान के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में लोगों ने विकास कार्यो की कोई भी मांग रखी उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने एक सासंद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के छः बार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस क्षेत्र में विकास की गति को जो धार दी थी, अब आने वाले समय मे विक्रमादित्य सिंह भी उस धार को ओर तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि मण्डी को केंद्रीय जोन का दर्जा, आईआई टी, नेरचौक मेडिकल कालेज वीरभद्र सिंह की ही सोच थी जो आज इस क्षेत्र में फलीभूत हुई है। उन्होंने कहा कि रोहतांग टनल कांग्रेस सरकार की देन रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस टनल को पैसा उपलब्ध करवाया था और तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस टनल की नींव रखी थी।

प्रतिभा सिंह ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी बताना चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में मण्डी संसदीय क्षेत्र को क्या कुछ नया दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मण्डी मुख्यालय के साथ विकास के मामले में भेदभाव ही नही किया बल्कि दो विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों से अन्याय किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नियत और नीति में खोट है और प्रदेश के लोग अब यह जान चुके है। प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार से लोगों को सचेत करने का आहवान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को सभी चारों सीटों के साथ साथ छः विधानसभा उप चुनावों में जीत हासिल करनी है। उन्होंने इसके लिये कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 9 मई को विक्रमादित्य सिंह के नामंकन पर मण्डी आने को भी कहा।

सेब बाग़बानों को 50 रुपए समर्थन मूल्य देने का झूठ बोल रहे जयराम:जगत नेगी

शिमला/शैल। बाग़वानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह बतायें किस सेब बाग़वान को भाजपा ने 50 रुपए का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जब भी चुनाव में हिमाचल आते हैं, तो सेब पर आयात शुल्क को दोगुना करने का जुमला बोल कर जाते हैं, लेकिन वास्तव में केंद्र सरकार ने आयात शुल्क को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है और हिमाचल प्रदेश के सेब बाग़बानों की कमर तोड़ दी है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमआईएस के तहत मात्र एक लाख रुपए का टोकन बजट रखा है और जयराम ठाकुर सेब बाग़बानों को 50 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेब बाग़बानों के साथ दग़ाबाज़ी करने के लिए भाजपा को सेब बाग़बानों को श्राप लगेगा। जयराम ठाकुर और भाजपा के गुनाहों को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आयात शुल्क घटाने से अफ़ग़ानिस्तान, ईरान से सेब देश में आ रहे हैं और आज कोल्ड स्टोर में रखे सेब के उचित दाम भी बाग़बानों को नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि आज कोल्ड स्टोर में रखी सेब की पेटी पर बाग़बानों को 800-1200 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका श्रेय भाजपा की केंद्र सरकार को जाता है। आयात शुल्क घटने से हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश के सेब बाग़बान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर पांच साल तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लेकिन एक भी नया प्रोजेक्ट सेब बाग़बानों के लिए नहीं लाये। जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को बतायें कि वह कौन सा प्रोजेक्ट सेब बाग़बानों के लिए पांच साल में लेकर आये।

बाग़वानी मंत्री ने कहा कि सेब बाग़बानों के हितों को देखते हुये वर्तमान प्रदेश सरकार ने अनेकों कदम उठाये हैं। किलो के हिसाब से सेब की बिक्री का काम जो पिछले कई वर्षो से नहीं हो पाया, वह काम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने किया है। यही नहीं, सेब बागवानों की वर्षो पुरानी मांग को पूरा करते हुये राज्य सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया है। सेब की खाद और कीटनाशकों पर मिलने वाली सब्सिडी को भाजपा सरकार ने बन्द कर दिया था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने फिर से सब्सिडी शुरू कर दी है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए रोज़ नया झूठ बोल रहे हैं। जिससे साफ़ पता लगता है कि भाजपा चुनाव में अपने हथियार डाल चुकी है। भाजपा का ख़रीद-फरोख्त करने वाला चेहरा जनता के सामने आ चुका है और भाजपा नेताओं को हार का डर सताने लगा है।

दिन–रात अपने मस्तिष्क को, उच्चकोटि के विचारो से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

घातक होंगे करोना वैक्सीन पर उठते सवाल

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इन चुनावों में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर जिस तरह की आक्रामकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने दिखाई है उससे कांग्रेस के घोषणा पत्र का पाठक बढ़ा है क्योंकि जो सवाल इस घोषणा पत्र पर उठाये जा रहे हैं उन मुद्दों का इस घोषणा पत्र में कोई जिक्र तक नहीं है। प्रधानमंत्री की आक्रामकता ने भाजपा और मोदी द्वारा पिछले दो चुनावों में किये गये वायदों की ओर देश का ध्यान आकर्षित कर लिया है। पिछले दो चुनावों में किये गये वायदों के अलावा इस दौरान घटी दो मुख्य घटनाओं की ओर भी आकर्षित कर लिया है। इस दौरान के नोटबंदी और फिर लॉकडाउन दो ऐसे घटनाक्रम है जिनका प्रभाव लंबे अरसे तक देश पर रहेगा। 2014 में सत्ता परिवर्तन अन्ना आंदोलन का एक बड़ा प्रतिफल रहा है। इस आंदोलन में तब की मनमोहन सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय बताकर लोकपाल की नियुक्ति अपनी मुख्य मांग बना दिया था। इस मांग के परिणाम स्वरुप लोकपाल विधेयक डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में ही पारित हो गया था और उस पर अमल मोदी सरकार में हुआ। लेकिन उस समय 1,76,000 करोड़ का जो 2जी स्कैम बड़ा मुद्दा बना था उस पर उसी विनोद राय ने जिसने यह स्कैम देश के सामने रखा था अदालत में इस कथित स्कैम पर यह कहा है कि यह स्कैम घटा ही नहीं था और इसमें आकलन की गलती लग गयी थी। विनोद एक सवैधानिक पद पर आसीन थें इसलिये उनके खिलाफ कोई करवाई नहीं हो सकी थी।

इसी तरह नोटबंदी के घोषित लाभों पर आज तक सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान आयी करोना महामारी ने देश को दो वर्ष तक लॉकडाउन में रखा। इस महामारी में अस्पताल तक खाली हो गये थे क्योंकि लोगों से सर्जरी तक को टालने की राय दी गयी थी। यह राय एक तरह का निर्देश बन गयी थी। महामारी को टालने के लिये लोगों ने ताली और थाली तक बजाने का प्रयोग किया। इस महामारी से बचने के लिये करोना वैक्सीन के दो दो टीके लोगों ने लगवाये। इन टीकों पर उस समय उठे सवाल सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे थे। यह टीके लगवाना कितना आवश्यक कर दिया गया था यह आम आदमी जानता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने यह कहा कि उसने यह वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं किया है। यह ऐच्छिक था और लोगों ने अपनी इच्छा से इसे लगवाया है। अब ब्रिटेन की एक अदालत में टीका बनाने वाली कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि इस टीके से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के खतरे हैं। कंपनी द्वारा स्वयं यहां साइड इफेक्ट होना स्वीकारने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उत्तराखंड इकाई ने राष्ट्रपति को मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन भेज कर इसकी निष्पक्ष जांच किये जाने की मांग की है। यह तथ्य सामने आने के बाद जिन लोगों ने यह टीका लगवाया उनमें एक डर का वातावरण फैल गया है। इस समय लोकसभा चुनावों के दौरान यह सामने आना एक नयी समस्या खड़ी करने का माध्यम बन सकता है। इस नयी आशंका पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई वक्तव्य जारी नहीं हुआ है।

उदासीन जनता, बेचैन भाजपा, यदि ऐसा ही रहा तो मोदी के परिवार का क्या होगा?

गौतम चौधरी

विगत कुछ दिनों से संसदीय आम चुनाव 2024 का आकलन कर रहा हूं। वैसे 2014 और 2019 का भी आम चुनाव तसल्ली से देखा था। उन दोनों चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तेबर के साथ चुनाव मैदान में डटी थी वह आक्रामकता इस बार देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है मेरा आकलन कमजोर हो लेकिन भाजपा के कई समर्थक इस चुनाव को लेकर आशंकित दिख रहे हैं। यदि भाजपा के नेताओं की बात करें तो उनमें इस चुनाव को लेकर घोर निराशा दिख रही है।

विगत दो–तीन चुनाव में झारखंड प्रदेश भाजपा का खास प्रबंधन देखने वाले एक नेता ने तो यहां तक बताया कि पूरे प्रदेश से जो रिपोर्ट आ रही है वह भाजपा के हित में नहीं है। उन्होंने एक बात यह भी बताया कि चतरा लोकसभा सीट पर जिस राजधानी यादव ने वहां के प्रत्याशी कालीचरण सिंह का विरोध किया उसे ही वहां के कई मामलों का प्रभारी बना दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि जिस काम की जिम्मेदारी राजधानी यादव को मिली है वह काम अभी तक प्रारंभ ही नहीं हो पाया है। मसलन, कालीचरण सिंह खुद की व्यवस्था नहीं किये होते तो उनका काम हो ही नहीं पाता और चुनाव हार भी सकते थे। प्रदेश की ओर से चतरा के प्रभारी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को बनाया गया है, जब इस संदर्भ में उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यालय में गलत रिपोर्टिंग हुई है। वहां किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। कमोबेस सभी संसदीय क्षेत्र की यही स्थिति है।

जानकार सूत्रों की मानें तो भाजपा अपनी ओर से सभी संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार सामग्री पहुंच चुकी है लेकिन उसे बांटने वाले नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इस बार जो प्रदेश की चुनाव अभियान संचालन समिति का गठन किया गया है उसमें से अधिक अनुभवहीन और काम करने में सक्षम नहीं हैं। प्रदेश भाजपा के कुछ क्षद्मपंथी जिन्हें टिकट की आस थी और टिकट प्राप्त करने में असफल रहे वे महत्वपूर्ण दायित्व में हैं। रांची और चतरा उनके टारगेट में हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस बार प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं तो अगली बार उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। इसलिए वे लगातार कन्नी काट रहे हैं। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि प्रदेश के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह यहां के लिये नये हैं और उन्हें झारखंड के विषय में मुकम्मल जानकारी नहीं है। यही स्थिति प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी है। सूत्रों से मिली खबर में बताया गया है कि विगत दिनों वाजपेयी ने चुनाव प्रबंधन को लेकर एक राज्यसभा सांसद को डांट भी पिलाई है। वैसे संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने प्रदेश कार्यालय मंत्री हेमंत दास को कई बार डांट चुके हैं लेकिन काम में किसी प्रकार का कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। इधर क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेन्द्र नाथ बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं।

प्रदेश का चुनाव मीडिया सेंटर शहर के नामी शमशान घाट हरमू स्थित मारू कंप्लेक्श में सिफ्ट कर दिया गया है। ज्योतिष के जानकार एक पंडित ने बताया कि शमशान घाट पर कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। वैसे भी मारू कंप्लेक्श को नकारात्मक ऊर्जा वाला माना जाता है। यही कारण है कि कंप्लेक्श अभी भी अधूरा पड़ा है। इस मामले को लेकर भी मीडिया के एक खास वर्ग में चर्चा आम है। विगत दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी ओर से आरोज्ञ भवन, बरियातू में समन्वय की एक बैठक बुलायी थी। उस बैठक में संघ के विविध क्षेत्र के प्रभारी और नेता मौजूद थे। वहां इस बात पर चर्चा हुई की आखिर वोटरों को कैसे निकाला जाये। इसी विषय में से एक विषय यह भी निकल कर सामने आया कि आखिर वोटरों को निकालने में पैसे भी खर्च होते हैं। वह कहां से प्राप्त होगा। इस बात पर संघ के एक अधिकारी ने पैसे उपलब्ध कराने की बात तो कही लेकिन नीचे के स्वयंसेवकों में अभी तक उत्साह का संचार नहीं दिख रहा है।

आम तौर पर देखने को मिल रहा है कि भाजपा वोटर के अंदर उदासीनता व्याप्त है। इसका सीधा कारण भावात्मक जुड़ाव की समाप्ति बताया जा रहा है। वो तमाम मुद्दे जिन पर भाजपा वोटर जोश से भर जाया करता था, वो पार्श्व में जा चुके हैं। धारा 370 हट चुका है, राम मंदिर बन चुका है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी लगभग समाप्त है। अब क्या? भाजपा वोटर किस बात पर सीना चौड़ा करें, अब किसके लिए बाहर निकले? उसके मतलब के सारे काम तो हो लिये।

जहां तक समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव की बात है तो यह मुद्दा भाजपा को अपने वोटरों से जोड़ने के लिए काफी नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले राम और धर्म की बात करते थे लेकिन अब भ्रष्टाचार और जाति पर उतर आये हैं। इसी से साबित हो रहा है कि भाजपा सभी मोर्चो पर कमजोर पड़ने लगी है। सिलिंडर, आवास, राशन ठीक है लेकिन कब तक इस पर वोट लिया जा सकता है? भाजपा के नेता अब मुद्दों को लेकर परेशान हैं।

दूसरी बात कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का कट्टर समर्थक भी इन दिनों अंदर से डगमगाया हुआ लग रहा है। वह भी जानता है कि काला धन, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि के मुद्दे पर भाजपा ने केवल बातें ही की है उस पर अमल अभी तक नहीं हो पाया है। क्षेत्र में जनता के सामने समर्थकों को ही जवाब देना होता है। बहस भी उन्हें ही करनी होती है। इस मामले में वे निरुत्तर हो जाते हैं। यही नहीं बाहर से आयातित नेता ने भी भाजपा के समर्थक और रूट वाले नेताओं को परेशान किया है। झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। झारखंड में भाजपा 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 13 उम्मीदवारों में से केवल लोहरदगा के उम्मीदवार समीर उरांव भाजपा के स्वाभाविक नेता हैं। शेष बाहर से आयातित हैं। कई नेता तो ऐसे हैं, जिन्होंने भाजपा और उनके नेताओं को गाली देकर पार्टी छोड़ गये थे। पलामू संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार वीडी राम पहले पुलिस अधिकारी थे और भाजपा विचारधारा से दूर–दूर का रिश्ता नहीं था। वही हाल निशिकांत दूबे का भी है। निशिकांत पहले अन्य विचारधारा की राजनीति में सक्रिय थे और बाद में भाजपा का दामन पकड़ा। इस बात को लेकर स्थानीय और रूट के नेता व समर्थक बेहद परेशान हैं। उन्हें यह लगने लगा है कि ऐसे में तो उनका नंबर कभी आयेगा ही नहीं। यह भाजपा समर्थकों को भी दिख रहा है कि 70 हजार करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार जैसे ही भाजपा की गोद में बैठा पाक साफ हो गया। इसके कई उदाहरण हैं। कई नेता तो आज दूसरी पार्टी से आये और आज ही उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया गया।

ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके कारण भाजपा समर्थकों में अवशाद है। नेताओं में घनघोर निराशा है और कार्यकर्ता घर बैठ गये हैं। हालांकि प्रतिपक्ष में भी वह दम नहीं है लेकिन यह भाजपा के हित में तो कतई नहीं है। आज नहीं तो कल इसका प्रतिफल भाजपा को भुगतना ही पड़ेगा।

मतदान के बदले में कुछ देने और प्रलोभन भ्रष्ट व्यवहार के बराबर:निर्वाचन आयोग

शिमला। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आड़ में मतदाताओं का विवरण प्राप्त करने से जुड़ी गतिविधियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के तहत रिश्वत देने का भ्रष्ट व्यवहार मानते हुए गंभीरता से लिया है। आयोग ने कहा है कि, 'कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो वैध सर्वेक्षणों तथा चुनाव के बाद लाभार्थी – उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं।

आयोग ने मौजूदा आम चुनाव 2024 में विभिन्न मामलों के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है इसमें सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे विज्ञापन/ सर्वेक्षण/ एप्प के जरिए चुनाव के बाद लाभार्थी – उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने जैसी गतिविधियां बंद करें।

आयोग ने कहा है कि चुनाव के बाद लाभ पाने के लिए पंजीकरण करने हेतु व्यक्तिगत मतदाताओं को आमंत्रित करने/ उनका आहवान करने का काम निर्वाचक और प्रस्तावित लाभ के बीच एक लेन – देन के रिश्ते की जरूरत का आभास पैदा कर सकता है, जिससे उन्हें एक विशेष तरीके से मतदान की व्यवस्था का प्रलोभन प्राप्त होगा।

आयोग ने ये माना है कि सामान्य चुनावी वादे जहां स्वीकार्यता के दायरे में आते हैं, वहीं आयोग ने ये भी कहा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ऐसी गतिविधियां भरोसेमंद सर्वेक्षणों और राजनीतिक लाभ के लिए कार्यक्रमों में लोगों को नामांकित करने के पक्षपाती प्रयासों के बीच अंतर को अस्पष्ट करती हैं। ये सब वैध सर्वेक्षणों का रूप लिए होती हैं कि वे संभावित व्यक्तिगत लाभों से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों या पार्टियों के एजेंडा के बारे में सूचित करने की गतिविधियां या प्रयास हैं।

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1), और धारा 171 (बी) आईपीसी जैसे वैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसे किसी भी विज्ञापन के खिलाफ उचित कारवाई करने का निर्देश दिया है।

तालिका नंबर एक:

अख़बार के विज्ञापन व्यक्तिगत मतदाताओं से मोबाइल पर मिस्ड कॉल देकर या टेलीफोन नंबर पर कॉल करके लाभ के लिए खुद को पंजीकृत करने को कहते हैं।

मतदाताओं के नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि जैसे विवरण मांगने वाले एक संलग्न फॉर्म के साथ संभावित व्यक्तिगत लाभों का विवरण देने वाले पर्चे के रूप में गारंटी कार्ड का वितरण।

जारी सरकारी व्यक्तिगत लाभ योजना के विस्तार के लिए संभावित लाभार्थियों के सामाजिक – आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर मतदाताओं का विवरण जैसे नाम, राशन कार्ड नंबर, पता, फोन नंबर, मतदान केंद्र संख्या, बैंक खाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या आदि मांगने वाले फॉर्म का वितरण।

राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं का विवरण जैसे नाम, पता, फोन नंबर, बूथ नंबर, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और नंबर आदि मांगने के लिए वेब प्लेटफॉर्म या वेब/मोबाइल एप्लिकेशन का प्रसार या प्रसार। इसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए निमंत्रण हो भी सकता है और नहीं भी लाभ या उनकी मतदान प्राथमिकता का खुलासा करना।

मौजूदा व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के बारे में समाचार पत्र के विज्ञापन या भौतिक फॉर्म के साथ – साथ पंजीकरण फॉर्म में मतदाता का विवरण जैसे नाम, पति/पिता का नाम, संपर्क नंबर, पता आदि मांगा जाता है।

पहले चरण में 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान

शिमला। आम चुनाव 2024 में, पहले चरण में 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 66.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। दोनों चरणों के लिए महिला – पुरुष मतदाताओं द्वारा मतदान के आंकड़े नीचे दिए गए है।

चरण	पुरुष मतदाताओं द्वारा मतदान	महिला मतदाताओं द्वारा मतदान	थर्ड जेंडर मतदाताओं द्वारा मतदान	कुल मतदान
चरण 1	66.22%	66.07%	31.32%	66.14%
चरण 2	66.99%	66.42%	23.86%	66.71%

चौथे चरण में 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे

शिमला। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 96 संसदीय सीटों के लिए कुल 4264 नामांकन दाखिल किए गये हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में सभी 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल, 2024 थी। दाखिल किए गए सभी नामांकनों की जांच के बाद, 1970 नामांकन वैध पाये गये।

मतदान के चौथे चरण में, तेलंगाना में सभी 17 संसदीय सीटों के लिए अधिकतम 1488 नामांकन फॉर्म भरे गए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में सभी 25 संसदीय क्षेत्रों से 1103 नामांकन फॉर्म भरे गये हैं। तेलंगाना के संसदीय क्षेत्र 7 – मलकजगिरि में सबसे अधिक 177 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुये। वहीं तेलंगाना में ही संसदीय क्षेत्र 13 – नलगोंडा और 14 – भोंगीर प्रत्येक में 114 नामांकन फॉर्म भरे गये हैं। चौथे चरण में संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 18 है।

दलों को उनके संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर फर्जी सामग्री हटानी होगी:ईसीआई

शिमला। चुनाव प्रचार के लिये सोशल मीडिया का उपयोग करते समय राजनीतिक दलों/ उनके प्रतिनिधियों द्वारा एमसीसी और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के कुछ उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए, आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया के जिम्मेदार तरीके से और नैतिक उपयोग के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी हितधारकों को समान अवसर मिले।

आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सूचनाओं को तोड़ने – मरोड़ने या गलत सूचना का प्रचार करने के लिए एआई आधारित साधनों के दुरुपयोग के खिलाफ दलों को चेतावनी दी है। ईसीआई मौजूदा कानूनी प्रावधानों को राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया है जो गलत सूचना के उपयोग और डीप फेक का उपयोग करके प्रतिरूपण (गलत पहचान) के खिलाफ नियामक ढांचे को नियंत्रित करते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, भारतीय दंड संहिता और दोहरे अधिनियमों अर्थात् जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 की रूपरेखा और आदर्श आचार संहिता के प्रावधान शामिल हैं।

मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर, अन्य निर्देशों के अलावा, दलों को विशेष रूप से डीप फेक ऑडियो/ वीडियो को प्रकाशित और प्रसारित करने से परहेज करने, किसी भी गलत सूचना या ऐसी जानकारी का प्रसार करने, जो स्पष्ट रूप से गलत, असत्य या भ्रामक प्रकृति की है, को पोस्ट करने से परहेज करने, महिलाओं के प्रति अपमानजनक सामग्री, अभियानों में बच्चों का उपयोग करने से बचने, जानवरों पर हिंसा या उनको नुकसान पहुंचाने से बचने का निर्देश दिया गया है।

दलों को ऐसी किसी भी सामग्री को उनके संज्ञान में लाने के तीन घंटे के भीतर तत्काल हटाने, अपनी पार्टी में जिम्मेदार व्यक्ति को चेतावनी देने, संबंधित मंचों पर गैरकानूनी जानकारी और नकली उपयोगकर्ता खातों की सूचनाएं देने और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3ए के तहत लगातार मुद्दों को शिकायत अपीलीय समिति (ग्रीवांस अपीली कमेटी) तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।

इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के आयोजन में 23 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे

शिमला। चुनावी विश्वनीयता और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में, निर्वाचन आयोग वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत में लोकतांत्रिक उत्कृष्टता को प्रथम दृष्टया देखने की पेशकश करते हुये देश में उच्चतम मानकों के साथ आम चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। निर्वाचन आयोग चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (आईईवीपी) के आयोजन के माध्यम से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

भागीदारी के पैमाने और परिमाण के मामले में यह ऐसा पहला आयोजन होगा जिसमें 23 देशों अर्थात – भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज़ गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, टयूनीशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया से विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के सदस्य और भूटान तथा इज़राइल की मीडिया टीमें भी भाग लेंगी।

4 मई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों के साथ – साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू 5 मई 2024 को इन विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद, ये प्रतिनिधि छोटे – छोटे समूहों में छः राज्यों – महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे तथा वहां के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। यह कार्यक्रम 9 मई, 2024 को समाप्त होगा।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 16वीं हितधारकों की बैठक का आयोजन किया

शिमला। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने 4 मई, 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अपनी 16वीं हितधारकों की बातचीत बैठक का आयोजन किया। हितधारकों की बैठक में सौर ऊर्जा, पवन, जल, जैव ऊर्जा, और नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियां सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में फैले व्यापार भागीदारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेष रूप से, यह 16 में से दूसरी बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गई। इसमें से 14 बैठकें वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थीं।

इस कार्यक्रम में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में इसके ऐतिहासिक वार्षिक प्रदर्शन पर बल दिया गया। चर्चा में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए की गई प्रमुख पहल, पिछली बातचीत बैठकों के सुझावों का कार्यान्वयन और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य की योजनाएं शामिल रहीं।

बैठक में उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) की टियर – 1 पूंजी 31 मार्च, 2024 तक 8,265.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह पर्याप्त पूंजी आधार परियोजना वित्तपोषण में बड़े निवेश को सक्षम बनाता है। कंपनी एकल उधारकर्ता को 2,480 करोड़ रुपये और उधारकर्ताओं के एक समूह को 4,133 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण करने में सक्षम है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) की निवल संपत्ति में वित्तीय वर्ष 2020 – 21 में 2,995 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में 8,559 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह इसकी वित्तीय ताकत और स्थिरता को प्रदर्शित करता है।

उधारकर्ताओं ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) को उसकी ऋण मंजूरी की सुव्यवस्थित प्रक्रिया और फेसलेस लेनदेन के लिए बधाई दी, जो व्यवसाय करने में सुगमता की सुविधा के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हितधारकों ने हाल ही में 'नवरत्न' का दर्जा हासिल करने और केवल 19 दिनों की अवधि में लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करने वाली पहली गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) की सराहना की।

हितधारकों को संबोधित करते हुए, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने व्यवसाय करने में सुगमता की सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने के महत्व को रेखांकित किया। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने स्थायी कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय उत्पादों को तैयार करने के प्रति कंपनी के समर्पण और भागीदारों की प्रतिक्रिया के आधार पर भारत सरकार द्वारा सीओपी – 26 में उल्लिखित दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए नए उत्पादों को पेश करने की उसकी तत्परता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर – जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

भाजपा ने खजाना लुटाकर प्रदेश को कंगाल कियाःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खू ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब मेंकांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुलतानपुरी के लिये चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश को कंगाल कर गयी है। सारा खजाना लुटा दिया गया, भाजपा ने चोर दरवाजे खोल रखे थे। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहते सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बने रहे। भाजपा ने आपदा में केवल राजनीति की और हमारी सरकार ने प्रभावित परिवारों को बसाने का काम किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दस सालों में भाजपा ने नया डिपार्टमेंट ऑपरेशन लोट्स बनाया है। कांग्रेस के छह भगौड़ू विधायक ईमान बेचकर चले गये। हमारे पास आज भी बहुमत है, सरकार को गिराने की कोशिश करने वाले जनता की नजरों में गिर चुके हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार ही होगा कि आज विधायक भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। स्पीकर ने उनसे पूछा कि क्यों इस्तीफा दिया, तो बस यही जवाब कि इस्तीफा स्वीकार कर लो।

ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि बिकाऊ विधायक जब गंगा में नहाने लगे तो गंगा मैया ने कहा तुम बड़े पापी हो, घर क्यों नहीं जा रहे। तुम्हारे पाप मेरे से नहीं धुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों की यह बिकने वाली व्यवस्था को जनता ही बदल सकती है, सरकार नहीं। बड़े-बड़े तानाशाहों को क्रांतियों के जरिये जनता ने ही बदला है, इसलिये जनता ही बिकाऊ विधायकों और उन्हें खरीदने वाली भाजपा को सबक सिखाये। मुझे कुर्सी से चिपकने का लालच नहीं है, जनता की सेवा करने के लिये सत्ता में आये हैं। भाजपा हिमाचल विरोधी पार्टी है, उसने आपदा में लोगों का साथ नहीं दिया, विशेष राहत पैकेज के लिए सरकार के साथ खड़ी नहीं हुई। छोटे-छोटे बच्चे आपदा में अपनी गुल्लक दे रहे थे तो मैंने अपनी जीवन भर की कमाई 51 लाख रुपये दान कर दी। हेलीकॉप्टर छोड़ दिया, 22 हजार परिवारों को बसाने के लिए 4500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। हम भाजपा की तरह भावनाओं को खरीदकर राजनीति नहीं करते।

शिमला संसदीय क्षेत्र के आपके सांसद आपदा में कहीं नहीं दिखे। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री से मिलकर हिमाचल की मदद करने की मांग तक नहीं की, संसद में आवाज तक नहीं उठाई। ऐसे सांसद को बदल लीजिए, विनोद सुल्तानपरी बीटेक हैं, आपदा में लोगों का साथ दिया, इन्हें चुनकर लोकसभा भेजिये। 15 महीने में हमारी सरकार ने जो काम किये हैं, उनके साथ चलिये। 1500 रुपये मासिक पेंशन के अप्रैल व मई के 3000 रुपये भी जून में मिल जाएंगे।

कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुलतानपुरी ने कहा कि सासंद सुरेश कश्यप संसद में मौन रहे। दस साल में सिर्फ दो सवाल पूछे। हमारा रिश्ता इस संसदीय क्षेत्र से पिता जी के समय से है, उनके किये काम हर जगह दिखते हैं। सुरेश कश्यप बतायें पच्छाद में राष्ट्रीय राजमार्ग और नालागढ़-बद्दी में ट्रेन कहां है।

इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, डिप्टी स्पीकर विनय कुमार, विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधायक किरनेश जंग, जिला अध्यक्ष इत्यादि मौजूद रहे।

डॉ. अतलु वर्मा ने हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाला

शिमला/शैल। डॉ. अतलु वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। डॉ. वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं जो 1991 बैच से हैं।

इन्होने एम.बी.बी.एस. और एम. बी.ए. की डिग्रियां हासिल की है तथा अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्टता का योगदान दिया है।

इन्होनें 11 अक्तूबर, 1992 को अपने करियर की शरुआत की तथा विभिन्न पदों पर अपने नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सेवाएं दी हैं। वह पुलिस महानिदेशक-राज्य गप्तुचर विभाग, पुलिस महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सीसीआई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, काननू और व्यवस्था अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचारी रोधी ब्यूरो, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय खण्ड, विशेष सचिव, गृह उप-पुलिस महानिरीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचारी रोधी ब्यूरो, उपनिदेशक, प्रवर्तन, भारत सरकार पुलिस अधीक्षक चंबा, बिलासपुर, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, ए.डी.सी. गवर्नर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला और कई अन्य पदों पर भी काम कर चुके है जो उनकी बहुमखुी प्रतिभा और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करता है।

अपने सेवाकाल के दौरान उन्होनें काननू एवं व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपर्णू योगदान दिया है। डॉ. वर्मा ने अपने कर्तव्य निष्ठा और नेतृत्व से सहकर्मियों और समदुाय के बीच सम्मान प्राप्त किया है।

हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में अपनी नई भूमिका में डॉ. अतलु वर्मा का संबंध उच्चतम पशेवरता और ईमानदारी के मानकों को बनाये रखने के लिए है। वह सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ निकटता से काम करने का उद्देश्य रखते हैं ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकें।

डॉ. अतलु वर्मा का पुलिस मुख्यालय में सभी उपस्थित अधिकारियों ने स्वागत किया व उनके सम्मान में गार्ड द्वारा सम्मान सलामी दी गई तथा सभी उच्च अधिकारियो की ओर से उन्हें उनके प्रयासों में सफलता की शभुकामनाएं दी।

नए मतदाओं का पंजीकरण कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करने पर दिया जाए विशेष बलःमनीष गर्ग

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, सहायक निर्वाचन अधिकारी, उप-मंडलाधिकारियों और हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के महाप्रबन्धक के साथ संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को फार्म-6 और फार्म-8 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने और निवास स्थान परिवर्तन के लिए), चुनावी फोटो पहचान पत्र (एपिक) वितरण, हथियार जमा करने और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित निगरानी करने और राज्य निर्वाचन विभाग को दैनिक आधार पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुछ जिलों में प्रपत्रों के निपटान संबंधित लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पते में बदलाव परिवर्तन, सुधार के दावों और आपत्तियों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अन्तिम तिथि 14 मई से पहले प्रपत्रों के निस्तारण पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त फार्म-6 में से लगभग 85 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है और चुनाव संबंधी जागरूकता प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले 7 दिनों के दौरान अधिकांश लंबित फार्म प्राप्त हुए हैं, जिनका निस्तारण कर शीघ्र मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सभी बूथों पर स्थायी सुनश्चित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसमें उचित संकेतक, पयेजल की सुविधा, उचित रोशनी, रैंप व शौचालय की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नए मानदंडों के अनुसार चुनाव डयूटी पर एक मतदाता को संबंधित एआरओ द्वारा स्थापित सुविधा केंद्र पर ही अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र प्रदान किया जायेगा और केवल सुविधा केन्द्र पर ही मतदान किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने, एआरओ द्वारा जारी चुनाव डयूटी प्रमाणपत्र, मतदाता सुविधा केन्द्रों में वोट डालने और मतपत्रों को समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुंचाने के चरणों के बारे विस्तारपूर्वक बताया गया है। यह सुविधा पुलिस कर्मियों, चालकों और परिचालकों, मतदान कर्मियों और चुनाव डयूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान दल प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित संबंधित मतदाता सुविधा केंद्रों पर 23 से 25 मई और 30 से 31 मई, 2024 को मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के अलावा चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाता पुलिस कर्मी, वीडियोग्राफर, चालक और परिचालक, सफाईकर्मी और चुनाव डयूटी में तैनात अन्य कर्मचारी मतदान तिथि से तीन दिन पूर्व 29 से 31 मई, 2024 तक आरओ एव एआरओ कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों में मतदान कर सकेंगे।

मनीष गर्ग ने चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाताओं को अपने डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए प्रत्येक सुविधा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में मतदान कक्ष और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने हथियार जमा करवाने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की और छूट प्राप्त हथियार धारकों को छोड़कर 7 मई, 2024 तक शत-प्रतिशत हथियार जमा करवाने का काम पूरा करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे राज्य में 84.4 प्रतिशत हथियार जमा करवाये जा चुके हैं।

उन्होंने सभी आरओ को नामांकन फार्म प्राप्त करने और जांच करने के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश भी दिए। प्रक्रिया के अनुसार आरओ 7 मई को प्रातः 11 बजे से पूर्व फार्म-1 में चुनाव की सूचना जारी करेंगे। उन्होंने नामांकन से संबंधित फार्म-3ए को प्रतिदिन अपडेट करने और दोपहर 3.15 बजे से पहले निर्वाचन पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आरओ नामांकन वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची वाले फार्म-7ए की सावधानीपूर्वक जांच करने और उसकी प्रतियां 17 मई को सायं 3.30 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। पोर्टल के माध्यम से सेवा कर्मियों के लिए ईटीपीबीएस भेजना और विभिन्न श्रेणियों के लिए डाक मतपत्रों के मुद्रण और वापसी के 48 घंटों के भीतर संबंधित एआरओ को भेजना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनावों के सुचारू संचालन के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के विभिन्न प्रश्नों का भी समाधान किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, नीलम दुल्टा और निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खेल छात्रावास में प्रवेश के लिए 6 मई से आयोजित होंगे खेल ट्रायल

शिमला/शैल। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि खेल छात्रावास ऊना, बिलासपुर तथा खेलो इंडिया उत्कृष्टता केन्द्र बिलासपुर में सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु इंदिरा स्टेडियम ऊना तथा लुहणू स्टेडियम बिलासपुर में स्पर्धावार ट्रायल का आयोजन करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास ऊना में लड़कों के प्रवेश हेतु वालीबाल और कुश्ती ट्रायल का 6 मई, 2024 तथा हाकी एवं जूडो ट्रायल का 7 मई, 2024 को प्रातः 10 बजे से आरम्भ किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास बिलासपुर में लड़कों एवं लड़कियों के प्रवेश हेतु एथलैटिक्स और लड़कों के लिए हैंडबाल ट्रायल का 9 मई, 2024 तथा लड़कों एवं लड़कियों के लिए कबड्डी ट्रायल 10 मई, 2024 को प्रातः 10 बजे से आरम्भ किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया उत्कृष्टता केन्द्र बिलासपुर तथा खेल छात्रावास बिलासपुर में लड़कों एवं लड़कियों के प्रवेश हेतु एथलैटिक्स, जूडो और बॉक्सिंग के लिए 11 मई तथा 12 मई, 2024 को प्रातः 10 बजे से ट्रायल आरम्भ किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि स्कूली खेल, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों तथा उदीयमान खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी संबंधित खिलाड़ी कार्यक्रमानुसार अपनी शैक्षणिक, आयु प्रमाणपत्र एवं खेल उपलब्धियों के मूल प्रमाणपत्रों का एक सैट सत्यापित छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित परीक्षण केन्द्र में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि खेल छात्रावास बिलासपुर तथा खेलो इंडिया उत्कृष्टता केन्द्र बिलासपुर हेतु खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाईन 8 मई, 2024 तक होगा। इसके लिए इच्छुक आवेदनकर्ता निर्धारित प्रपत्र विभागीय वैबसाइट himachal.nic.in/yss से डाउनलोड करके आवेदन पत्र को भरकर संबंधित जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, बिलासपुर तथा ऊना को dyssobilaspur@gmail.com तथा Dscuna@gmail.com पर भेज सकते हैं।

इसके अतिरिक्त ऑफलाईन पंजीकरण केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी कारणवश ऑनलाईन पंजीकरण नहीं कर पाएंगें। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कार्यक्रमानुसार प्रातः 9बजे से लुहणू स्टेडियम, बिलासपुर तथा इंदिरा स्टेडियम ऊना में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का टीए/डीए नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए खिलाड़ियों की आयु सीमा 13 से 19 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 13 वर्ष से 15 वर्ष आयुवर्ग के खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। चुने हुए खिलाड़ियों को मुफ्त आवास, भोजन, चिकित्सा, बीमा, खेल किट, खेल सामान व आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और खिलाड़ी किसी भी स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि चयन प्रतियोगिता में प्रवेश हेतु 13 वर्ष आयुवर्ग के आवेदनकर्ता के लिए लम्बाई 158 सेंटीमीटर एवं वजन 43 किलोग्राम, 14 वर्ष आयुवर्ग के लिए 164 सेंटीमीटर एवं वजन 49 किलोग्राम और 15 वर्ष आयुवर्ग के लिए लम्बाई 165 सेंटीमीटर और 50 किलोग्राम वजन का न्यूनतम शारीरिक मापदंड निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित खेलों में राज्य, राष्ट्रीय सब जूनियर, जूनियर व स्कूली स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी न्यूनतम शारीरिक मापदंड पूरा न करने की स्थिति में भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया:मीनाक्षी लेखी

शिमला/शैल। भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा की भारतीय जनता पार्टी अपना लोक सभा का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गई है पर कांग्रेस सरकार अपने पिछले 16 महीने का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पायी है, यह सुख

की नहीं दुख की सरकार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। यह परिवर्तन सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, चाहे वह रेलवे हो, राजमार्ग हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा आदि हो। यह प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और 2014 से 2024 जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रही भारत ने अपने दो युगों को साफ-साफ देखा है एक युग जो विनाशकाल की दृष्टि से देखा जा सकता है और दूसरा अमृतकाल।

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मॉर्गन स्टैनली जो की एक विश्व के अग्रणी वित्तीय विश्लेषक है उनकी टिप्पणी के मुताबिक यूपीए के दौरान भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था थी और मोदी सरकार में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने 2021 और 2022 में दो वर्षो की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बाद 2023 में भी अपनी निरंतर एवं तेज रफ्तार को कायम रखा है। भारत 2030 तक 7.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

उन्होंने कहा की नल जल कनेक्शन की दृष्टि से देश में 2014 तक 3.2 करोड़ घरों को नल पहुंचाया गया था और 2024 में देश के 12.7 करोड़ घरों तक नल पहुंचा दिया गया है। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2014 तक देश में 1.79 करोड़ घरों का निर्माण हुआ था अब 2024 में इन घरों को संख्या 2.9 करोड़ पहुंच गई है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश में 2023 तक 9.6 करोड़ घरों तक मोदी सरकार ने गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का चिकित्सा बीमा प्रदान किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत 278 अस्पताल पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत पिछले तीन साल में 4.85 लाख लोगों से ज्यादा का इलाज किया गया है। नवंबर 2023 तक 78 हजार 365 नए कार्ड भी बने थे। ऐसे में इस योजना का लाभ लोगों का न मिलने पर अब हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। इन योजनाओं के 300 करोड़ से अधिक पैसे प्रदेश सरकार ने अभी तक दिए नहीं है, जिसके कारण जो मुफ्त इलाज गरीबों को मिलता था वह नहीं मिल पा रहा है।

यहां तक की 1200 करोड़ के ऐसे कार्य है जिनके पैसे जमा न करने के कारण व सरेंडर हो गये हैं इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अनेकों सड़के भी है। उन्होंने कहा कि अपने 16 महीने के कार्यकाल में इस सरकार ने 25000 करोड़ का ऋण ले लिया हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने 2012 से 2017 के बीच केवल 17829 करोड़ का ऋण लिया था।

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बिजली में सौभाग्य योजना, उदय योजना, एलईडी योजना यह सब प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रहीं हैं, जिससे गरीब और जरुरतमंद घरों को अच्छी क्वालिटी की बिजली हर समय उपलब्ध हो सके। आज 6 लाख से ज्यादा देश के हर गांव में इंटरनेट की सुविधा चल रही है। पहले तो बिजली ही ठीक नहीं चलती थी तो इन्टरनेट आप क्या चलाएंगे? फ़ोन कैसे चलाएंगे?

हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी उसने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी और कांग्रेस ने वादा किया था कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, परन्तु 16 महीने निकल गये वो 300 यूनिट कहां है?

कांग्रेस ने आपदा में भी किया भाई-भतीजावादः अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसियों की ब्यानबाजी का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक पढ़ने लिखने

की आदत नहीं है इसीलिए उन्हें भाजपा का विकास और अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता। हमने मात्र 1 वर्ष में 20 हजार ग्रामीण आवास मंजूर कराये हैं। आपदा के समय त्वरित तौर पर 1762 करोड़ रूपये दिये गये। हमने मनरेगा में भी अलग से पैसे दिये लेकिन कांग्रेस ने तिरपाल बांटने में भी बंदर बांट करते हुए यह देखा कि कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है। कांग्रेसी नेताओं ने तिरपाल बंटाई में भी भाई-भतीजावाद को प्राथमिकता दी। इन्होंने खुद तो आपदा पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया और केंद्र से मिली मदद का भी उपयोग नहीं कर पाये।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज चुनाव परिणाम से पहले हीं कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है इसलिए वह कभी ईवीएम तो कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी कुछ और पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस तो झूठ, भय और भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर अब डीप फेक का उपयोग कर रही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा से पहले कोविड काल में भी मैंने सिर्फ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, पीपीई किट, मास्क और जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई थीं। हमारी संस्कृति आपदा में राजनीति करने की नहीं हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1762 करोड रुपए के एम्स अस्पताल के बाद किसे पता था कि हम अपने ऊना के लिए 500 करोड़ का पीजीआई अस्पताल भी मंजूर करवा लेंगे। लेकिन यह सब हमने मोदी जी के नेतृत्व में संभव कराया है। आज हमारा संसदीय क्षेत्र मेडिकल टूरिज्म का हब बनने वाला है। इससे यहां रोजगार और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार आज हमारे यहां सभी बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं और अब प्रदेश का पहला सिंथेटिक हॉकी फील्ड भी हम ऊना में हीं बनाने जा रहे हैं। आज हमने दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुंचा दी है और उसका विद्युतीकरण भी किया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार में मैं यहां से सांसद था तब मैं लड़कर यहां प्रोजेक्ट लाता था तब भी उस समय की कांग्रेस की सरकार उन्हें लागू नहीं करती थी। लेकिन मोदी जी की सरकार में मैंने प्रोजेक्ट भी लाया और जयराम सरकार में उसे लागू भी कराया। इसी प्रकार आज अगर हिमाचल के उद्योगों में 7 लाख लोग कार्यरत हैं तो वह श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार और प्रेम कुमार धूमल की सरकार में संभव हुआ था। यह औद्योगिक पैकेज अटल और धूमल जी की सरकार के समय 2002 में मिला था। उसके बाद से अगर कोई औद्योगिक पैकेज मिला है तो बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में मिला है जो मोदी जी ने दिया है। इससे 30000 और लोगों को रोजगार मिलेगा।

भाजपा प्रत्याशीयों के नामांकन भरने का शेड्यूल जारी:बिंदल

शिमला/शैल। कांग्रेस ने जो अपना मेनिफेस्टो जारी किया है उसमें बहुसंख्यक वाद को प्राथमिकता देते हुए विशेष बल देने की बात की है जो कि बिल्कुल अमान्य है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बहुसंख्यकवाद को और अल्पसंख्यक को साथ उसको मिलाते हैं तो उस बहुत संख्या का अर्थ है हिंदू और बड़े स्पष्ट बहुसंख्यक का अर्थ हिंदू है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट शब्दों में हाइलाइटेड पैरा के अंदर बहुसंख्यकवाद नहीं चलने दिया जायेगा अर्थात हिंदुत्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शब्दों को पूरा किया जायेगा, जिसमें उन्होंने कहा था की भारत के संसाधनों पर पहला हक़ अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। हिंदू समुदाय के लोगों को उनकी जातियों में बांट कर के देखा जायेगा। जातिगत जनगणना के अन्दर बांट कर के उनको रखा जायेगा। ओबीसी आरक्षण में से आरक्षण काटकर मुस्लिम को दिया जायेगा। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसका समर्थन राहुल गाँधी करते है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी अपना नामांकन इन तिथियों को भरने जा रहें है लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि 10 मई- डॉ. राजीव भारद्वाज, कांगड़ा, 13 मई- अनुराग ठाकुर, हमीरपुर और सुरेश कश्यप, शिमला, 14 मई- कंगना रनौत, मंडी इसी प्रकार हिमाचल विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि 9 मई- रवि ठाकुर (लाहौल स्पीति) 10 मई- आईडी लखनपाल (बड़सर), राजिन्द्र राणा (सुजानपुर), देविंदर कुमार भुट्टो (कुटलैहड़)14 मई- सुधीर शर्मा (धर्मशाला) गगरेट से चैतन्य शर्मा की नामंकन तिथि कुछ दिन में तय होगी।

उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 50 से ज्यादा पन्ना प्रमुख कार्यक्रम हो चुके है जिसमें 140000 से अधिक पन्ना प्रमुख भाग ले चुके है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सरकार चुनावी मुद्दों से भाग रही है और उनके पास अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वह जनता तक पहुंचा सके। इसलिए योजना पूर्वक मुख्यमंत्री अभद्र ब्यानबाजी कर रहे है ब्यान जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। कभी काला नाग, भेड़ बकरी बोल रहे हैं और विक्रमादित्य तो कभी मेंढक शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं। प्रतिभा सिंह तो हमारे प्रत्याशी को किसी चीज के साथ तुलना कर देते है।

उन्होंने कहा जनता मुख्यमंत्री व प्रियंका गाँधी से सवाल पूछ रही है कि महिलाओं को सम्मान राशि कब मिलेगी? कांग्रेस सरकार ने फार्म भरवा दिए परन्तु एक पैसा भी नहीं मिला, दूसरा चुनाव आ गया। अब फिर फार्म भरवा रहे हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती हैं पहले वाले 2022 के फार्म कौन सी कबाड़ी की दुकान पर बेचें? और 2024 के चुनाव फार्म बेचने का ठेका कौन से कबाड़ी को दिया है? ये हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री से जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता कांग्रेस से जानना चाहती है कि पहली कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, वो नौकरी कहां गई? नौकरी तो दूर परन्तु नौकरी देने वाले संस्थान ही बंद कर दिये और तो और विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री इस बात से ही पलट गये कि उन्होंने पहले साल में 1 लाख सरकारी नौकरीया देने का वायदा जनता से किया था। ऐसे में जनता इन पर क्यों विश्वास करें। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 10 हजार कोविड कर्मियों को नौकरी से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर आये दिन अर्थिक बोझ डालने का कार्य यह सरकार कर रही हैं। 25 हजार करोड़ रूपये का कर्ज डेढ़ साल में ले लिया, लेकिन विकास के नाम के ऊपर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 16 महीनां का समय सिर्फ भाजपा को गाली देने में बिता दिया और चुनाव भी बीजेपी को गाली देकर के ही लड़ रहे हैं।

सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन पर नहीं, सत्ता परिवर्तन की राह पर:विपिन परमार

शिमला/शैल। कांगड़ा-चम्बा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी एवं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुये कहा कि इस सुख की सरकार से जनता दुखी हो चुकी है। व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सत्ता परिर्वतन की राह पर चल पड़े है। जनता चाहती है कि इस कांग्रेस सरकार से अब जल्द से जल्द छुटकारा मिले। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला भवन निर्माण को लेकर विपिन सिंह परमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे शायद कहीं और ले जाना चाहते हैं, यही कारंण है कि अभी तक वे 30 करोड़ रुपया जमा नही करवा पाये हैं। मुख्यमंत्री कांगड़ा की जनता के हकों को छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी 6 जून को धर्मशाला में सीयू में दीक्षांत समारोह में भाग लेने आ रही हैं। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वे प्रदेश सरकार का मार्ग दिखाये ताकि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द शुरु हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता के हकों की बात कर रही है, जबकि दूरी और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम को आरक्षण देने तथा ओबीसी कोटे को कम करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदुत्व को खत्म करने की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है की मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है।

उन्होंने कहा कांग्रेस जाति के आधार पर जनगणना की बात कर रही है। कांग्रेस की नियत में खोट है। वे विभाजन की बल पर अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, जिसे देश के लोग कभी स्वीकार नही करेंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चम्बा संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार ने 36 सालों में कार्यकर्ता के रुप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास किया है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नही है। कांग्रेस उधार के लोगों को टिकट दे रही है। आनंद शर्मा जब केंद्र में मंत्री थे जो उन्होंने हिमाचल के हकों को अनदेखा किया। उन्होंने कहा आनंद शर्मा ने दिल्ली में बैठकर ही राजनीति की है। हिमाचल से उनका कोई लेना देना नही है। इस मौके पर उनके साथ कांगड़ा के विधायक पवन काजल, कुलभुषण नाग, राकेश शर्मा, विश्व चक्षु व संजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस के विद्रोह का केन्द्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ही क्यों बना?

- वित्तीय संकट के चलते सरकार अपने खर्चे क्यों कम नहीं कर पायी?
- जब जल उपकर अधिनियम ही असंवैधानिक है तो उसी के तहत बना आयोग सही कैसे?

शिमला/शैल। कांग्रेस अभी तक धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिये अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पायी है। पांच उप चुनाव के लिये जो उम्मीदवार घोषित किए गये हैं उसमें गगरेट और सुजानपुर में भाजपा से कांग्रेस में आये नेताओं को टिकट दिये गये हैं। बडसर, कुटलैहड और लाहौल स्पीति में ही कांग्रेस के पुराने लोगों पर भरोसा किया गया है। किसकी जीत होगी इसका आकलन अभी करना जल्दबाजी होगी। यह सही है कि उपचुनाव सरकार का भविष्य तय करेंगे। इसलिए अभी यह चर्चा करना प्रासंगिक होगा कि इस समय प्रदेश के बड़े मुद्दे क्या हैं। क्या सरकार और विपक्ष प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिये तैयार है या फिर इस उप चुनाव के लिये अलग से मुद्दे तैयार किये जायेंगे।

प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने पन्द्रह माह हो गये हैं। जब सरकार ने कार्यभार संभाला था तब प्रदेश की वित्तीय स्थिति श्रीलंका जैसी होने की चेतावनी जारी की गयी थी। प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप पूर्व की सरकार पर लगाया गया। वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया। पिछली सरकार द्वारा अंतिम छः माह में खोले गये हजार के करीब संस्थान बंद कर दिये गये। हमीरपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तक भ्रष्टाचार और प्रश्न पत्र बिकने के आरोप पर भंग कर दिया गया। प्रदेश की जनता सरकार के इन फैसलों को जायज मानकर चुप रही। लेकिन जैसे ही सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी और करीब डेढ़ दर्जन के करीब ओ. एस.डी. और सलाहकार कैबिनेट रैंक में नियुक्त कर दिये तब सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठने शुरू हुये। कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों में दी गई गारंटीयों पर सवाल उठने शुरू हुये। क्योंकि खराब वित्तीय स्थिति में कोई भी व्यक्ति, संस्थान या सरकार अवांच्छित खर्च नहीं बढ़ाते। सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन के लिये आज तक किसी को नोटिस तक जारी नहीं किया है। कांग्रेस द्वारा चुनावों में जारी किये गये आरोप पत्र पर कोई कारवाई नहीं हुई है।

इस समय बेरोजगारी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पिछले दिनों बिलासपुर में एक युवक द्वारा नौकरी न मिलने पर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या युवा वोटरों की संख्या से बढ़ गयी है। सरकार आय के साधन बढ़ाने के लिए परोक्ष/अपरोक्ष में टैक्स लगाने के अतिरिक्त और कुछ सोच नहीं पा रही है। सरकार ने चार हजार करोड़ का राजस्व बढ़ाने के नाम पर बिजली उत्पादन कंपनियों पर जल उपकर लगाने के लिये विधेयक पारित किया और एक जल उपकर आयोग तक स्थापित कर लिया। लेकिन जैसे ही यह मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो अदालत ने जल उपकर अधिनियम को असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर दिया। परन्तु सरकार ने इसी अधिनियम के तहत स्थापित हुये आयोग को भंग नहीं किया है। इससे सरकार की नीयत पर अनचाहे ही सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिये हर सेवा और वस्तु का शुल्क बढ़ाया है। परन्तु उसी अनुपात में अपने खर्चो पर लगाम नहीं लगाई है। सरकार एक तरफ राजस्व लोक अदालतें लगाकर लोगों को राजस्व मामलों में राहत देने का दावा कर रही है और दूसरी ओर इसी राजस्व में ई-फाइलिंग, ई -रजिस्ट्रेशन आदि करके हर सेवा पहले से कई गुना महंगी कर दी है।

इस समय व्यवहारिक रूप से आम आदमी को रोजगार से लेकर किसी भी अन्य मामले में भाषणों में घोषित हुई राहतें जमीन पर नहीं मिली है। इस समय चुनावों में उम्मीदवार तलाशने में लग रहे समय से ही यह सवाल उठ गया है कि जब लोकसभा चुनाव होने तो तय ही था तो इसके उम्मीदवारों के लिये इतना समय क्यों लगा दिया गया? क्या इससे यह संदेश नहीं गया कि सरकार और संगठन में सब सही नहीं चल रहा है। इस समय मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी बागीयों पर बिकने का आरोप लगाकर उपचुनाव थोपने की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बागी मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले डालकर उन्हें घेरने की रणनीति पर चल रहे हैं उससे सारी बाजी पलटने की संभावना प्रबल होती जा रही है। यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि इस विद्रोह का केंद्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ही क्यों बना? आम आदमी यह मानने को तैयार नहीं है कि इतने बड़े विद्रोह कि कोई भी पूर्व सूचना सरकार को नहीं हो पायी? जबकि हाईकमान के संज्ञान में यह रोष बराबर रहा है। वरिष्ठ मंत्री चन्द्र कुमार ने जिस तरह से इस संकट के लिये मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को दोषी माना है वह एक और बड़े संकट की आहट माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि कांग्रेस के संकट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर आ गयी तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे।

क्या 25000 करोड़ का कर्ज करके 1500 की पैन्शन बांटना सही है

- कर्ज के इस आरोप पर सरकार की चुप्पी क्यों
- जब विभाग में आठ पैन्शन योजनाएं चल रही हैं तो नयी की आवश्यकता क्यों?

शिमला/शैल। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को पन्द्रह पन्द्रह सौ रुपए प्रतिमाह देने की गारन्टी दी थी। यह गारंटी देते हुये यह नहीं बताया गया था कि वह पन्द्रह सौ कब से देने शुरू किये जाएंगे। जब इस गारन्टी पर सवाल उठने शुरू हुये तो इसे लाहौल-स्पीति से लागू कर दिये जाने की घोषणा कर दी गयी। इसी के साथ यह भी कहा गया कि बाकी प्रदेश में भी इसे शीघ्र लागू कर दिया जायेगा। इसी दौरान इस आश्य की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी। अधिसूचना के साथ वह फॉर्म जारी किया गया जो पन्द्रह सौ पाने के लिए भरा जाना है। इस फॉर्म में पात्रता के लिये कई सारे राइटर जोड़ दिये गये हैं। इन चुनावों की घोषणा के बाद जब यह फॉर्म भरे जाने लगे तो इसकी चुनाव आयोग में शिकायत हो गयी और यह फॉर्म भरने का काम रुक गया। अब यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है कि भाजपा महिलाओं को यह सहायता दिये जाने का विरोध कर रही है। सरकार के पास यह सहायता दिये जाने के लिये संसाधन कहां से आयेंगे? क्या कर्ज लेकर यह सहायता दी जायेगी या आम आदमी पर करों का बोझ डालकर यह सवाल भी चर्चा में आने लगा है। इन चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 28 लाख है। इसलिए पन्द्रह सौ रूपये को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण से सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं को समझने की आवश्यकता है।

इस समय जनकल्याण के नाम पर आठ पैन्शन योजनाएं चल रही हैं। यह योजनाएं हैं वृद्धावस्था पैन्शन योजना, दिव्यांग राहत भत्ता, विधवा/परित्यक्ता /एकल नारी पैन्शन, कुष्ठ रोगी पुनर्वास योजना, ट्रांसजैण्डर पैन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था (बी.पी.एल.) त्रैमासिक वित्तीय सहायता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पैन्शन योजना। इन सारी पैन्शन योजनाओं के लाभार्थीयों की संख्या 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 7,83,917 है। इसी सर्वेक्षण के मुताबिक 15-5-23 से लाहौल स्पीति में दिये जा रहे 1500 रुपए के लाभार्थियों की संख्या 803 है। इन योजनाओं के तहत एक हजार, ग्यारह सौ पचास और सत्रह सौ रूपये दिये जा रहे हैं। सरकार की इन योजनाओं पर नजर डालने से यह सवाल उभरता है कि इन योजनाओं से कौन सी पात्र महिला छूट गयी होगी जिसे अब पन्द्रह सौ के दायरे में लाया जायेगा। फिर यह भी कहा गया कि सभी की पैन्शन राशि पन्द्रह सौ कर दी जायेगी। इसमें एक हजार या ग्यारह सौ पचास पाने वाले को तो पन्द्रह सौ मिलने से कुछ सहायता बढ़ जायेगी। लेकिन क्या सत्रह सौ पाने वाले के दो सौ कम कर दिये जाएंगे यह स्पष्ट नहीं है।

इस समय सरकार पन्द्रह माह के कार्यकाल में 25000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और 6200 करोड़ और लेने जा रहे हैं। यह आरोप भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने लगाया है। डॉ. राजीव बिंदल पहले भी आर.टी.आई. के माध्यम से ली गयी सूचना के आधार पर कर्ज के आंकड़े जारी कर चुके हैं। डॉ. बिंदल द्वारा जारी कर्ज के इन आंकड़ों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि क्या कर्ज लेकर इस तरह की राहत पहुंचाना जायज है? क्योंकि जब कर्ज लेकर राहत बांटी जाती है तब कर्ज के कारण बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में यह राहत अर्थहीन होकर रह जाती है। इस समय इतना कर्ज लेकर भी सरकार कर्मचारियों के बकाये की ही अदायगी नहीं कर पायी है। इसलिए कर्ज लेकर राहत बांटने के सिद्धांत पर एक सार्वजनिक बहस में फैसला लिया जाना चाहिए। क्योंकि पन्द्रह माह में 25000 करोड़ का कर्ज एक बड़ा आरोप है। सरकार की खामोशी से यह और गंभीर हो जाता है।